



भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) COMMUNIST PARTY OF INDIA(MAOIST)

दिनांक: 19 सितंबर 2013

प्रेस रिलीज

‘जनता से दंड वसूल करना’ – कमिश्नर सत्यपालसिंग की यह बौखलाहट है!

अंग्रेज गये लेकिन उनके पालतु कुत्ते भारत में अभी भी मौजूद हैं। भौंकते-भौंकते जनता के दिन की चैन और रातों की नींद हराम कर दी है। इन साम्राज्यवादी लायसन्सधारी कुत्तों का बंदोबस्त जब तक नहीं किया जाता, तब तक देश की जनता सही मायने में आजाद हवाओं में सांस नहीं ले सकती। मुंबई के कमिश्नर सत्यपाल सिंग ने माओवादी क्रांतिकारीयों को मदद करने वाले गांव वालों पर दंड लगाना और उनको संचारबंदी लगाने की बात कही है। दिनांक 19 अगस्त 2013 को प्रसार माध्यमों में यह खबर छपी है। यह बयान पगलाये कुत्ते के जैसा है। और क्या ना हो, क्योंकि उनके अर्धसैनिक बल, कमांडो बल, पुलिस के ही साधे लिबाज के क्रूर हत्यारे गिरोह, तरह-तरह के लालच और फूसलाने के हथखंडे सब नाकाम साबित हो रहे हैं। पुलिस के भत्तों में और खुफियाँ मुखबिर गिरोह तयार करने में करोड़ों रुपये बर्बाद करने के बाद भी माओवादी और जनता इनके बिच विभाजन करने का सत्ताधारी वर्ग का धिनौना षडयंत्र असफल होते देख बौखलाहट से जनतापर टुट पड़ने का और एक पर्ईत्रा सत्यपालसिंग पेश कर रहे हैं।

उनके दमन के हर पहलु के खिलाफ आदिवासी और गैर आदिवासी जनता अपने प्यारे बच्चों के द्वारा गठीत पी.एल.जी.ए. के साथ मिलकर डटकर प्रतिरोध कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा घर जलाना, खेत बर्बाद करना, जीने के साधनों को तहस-नहस करना, महिलाओंपर बलात्कार करना, झुठी मुठभेड़ों में मार डालना, आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं के परिजनों को धमकाकर सरेंडर करवाने प्रसार माध्यमों के सामने पेश करना आदि हमलों के बावजूद महाराष्ट्र सरकार भारतिय दलालों और अमरिकन आकाओं के आदेशों को उनके समयानुसार अमंल नहीं कर पाये इसलिए उनकी खिज सत्यपालसिंह के मुहँ से बाहर निकल रही है। गडचिरोली जिले की बहुमुल्य खनिज संपदा और सागवान और अन्य जंगल उत्पाद को हडपने के लिए आदिवासीयों का सफाया करना यह टास्क पर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है। पिछले छह माह में गडचिरोली जिले में 28 लोगों को झुठी मुठभेड़ों में मार डाला जिसमें 17 महीलाएँ हैं। क्या माओवादी, क्या बंदुकधारी, क्या महिलाएँ-बच्चे और क्या आम जनता कोई भी नहीं बचा है। 19 मई को तो जनता ने महाराष्ट्र सरकार की हैवानियत आँखों से देखी, जब एक 15 साल के बालक रमेश को हेट्टेडकसा गांव में फायरिंग के वक्त जखमी हालात में गिरपतार कर करीबन 3 कि.मी. कुमुडपार गांव ले जाकर डंडे से पिट-पिट कर मार डाला। दरिंदगी का आलम यह है कि, हत्याएँ करके मृतकों के खून से लथपथ छिन्न-विछिन्न चेहरों की तस्विरें खिंचकर उसके बड़े-बड़े फ्लैक्सों बँनर बनाकर गांवों में लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का यह वहशी फासीवादी चेहरा देखकर घिन आती है। इंसानीयत के मुल्य और मानवता के गरिमा की इस कदर बेइज्जती को देखकर आम इन्सान तो क्या मानवता की गरिमा को उंचा उठाने वाले महाराष्ट्र के सपुत महामानव महात्मा फुले और बाबासाहेब आंबेडकर भी यदी होते तो उनकी आँखों से आँसु छलकते और निश्चित ही इस दरिंदगी और जुल्म के खिलाफ हथियार बंद संघर्ष का ऐलान करते।

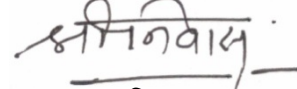
सत्यपालसिंग सनकी नहीं है। उच्च शिक्षित है, फिरभी वे गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे हैं क्योंकि वह साम्राज्यवादी दलालों की सत्ता का ठोस कलपुर्जा है। उनके बोल दर असल सरकारकी नीति को ही उजागर कर रहे हैं। ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ के बारे में देश के बुद्धिजीवियोंने इसे सरकार का ‘जनता पर युध्द’ करार दिया इस बात को सत्यपाल सिंग का वक्तव्य मजबुती प्रदान करता है।

सत्यपाल सभी गांववालों को दंड देने कि भाषा बोलकर, डिआयजी रविंद्र कदम को जनता पर युद्ध की आक्रमकता और बढ़ाने को ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह दोनो एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं जो सरकार की जनविरोधी नीति को अमल करने के कलपुर्जे हैं। दरअसल रविंद्र कदम सत्यपाल सिंग से कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। सत्यपाल सिंग दंड कि बात करता है। रविंद्र कदम गडचिरोली जिले में आदिवासीयों की थंडे दिमाख से सिधे हत्याएँ कर रहे हैं। इन अफसरों के बयानों से महाराष्ट्र सरकार का वहशीपन खुलकर जनता के सामने नंगा हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मौत के खेल की प्रतियोगिताएँ जारी की हैं। जिसमें आदिवासीयों जो जितनी जल्दी ज्यादा संख्या में खत्म करेगा वह पुरस्कार और प्रमोशन का पात्र होता है। अंग्रेज लोग या पुराने जमाने के राजा-महाराजा जानवर और पंछी को जिस तरह शिकार करके अपना शौक करते थे वैसे ही यहाँ के आदिवासीयों को वे पशु समजते हैं। 'नवजिवन योजना' जैसे मिडीया स्टंट इस पाशविक मौत के खेल को मानविय चेहरा प्रदान करने चाल है।

इन दोनो वरिष्ठ पुलिस अफसरों की मिडीया की स्टंटबाजी, आर्थिक संकट से बेहालहुए और बचने के लिए की जा रही सत्ताधारी वर्ग की फडफडाहट कि अभिव्यक्ति है। वे इस संकट से बाहर निकलने जल-जंगल-जमिन पर कब्जा चाहते हैं। खदानें खोलना चाहते हैं, सागवान और पर्यटन के लिए जंगल पर पुरा कब्जा चाहते हैं। उनके इस लुटेरे इरादों के आडे आदिवासी और वनों में रहनेवाली जनता आ हरी है इसलिए उनको रौंद रहे हैं। इससे आदिवासी और आम जनता के अस्मिता और अस्तित्व का सवाल खडा हो गया है।

यह पुलिस के बडे अफसर जो अमरिकन 'लो इंटेन्सीटी कॉम्प्लीक्ट' (एल.आय.सी.) के नाम से कुख्यात मिलीटरी नीति की ट्रेनिंग लिए हुए हैं। जिसके दिशा निर्देश यह है कि, जनता पर इतना दमन करो कि, जनता केवल अपनी जान को बचाने की ही सोचें, समाज या जल-जंगल-जमिन की ना सोचें। सत्ता पर बैठा वर्ग और मुनाफे के लिए मानवीय मुल्य, मानवीय गरिमा, समाज और प्रकृती सबको ध्वस्त करने पर उतारु है। इतिहास में अमेरिका में कोलंबसने जिस तरह वहाँ के 1 करोड रेड इंडियन आदिवासीयों की हत्या की थी, उसी तरह आज उसी के यह दलाल भारत में कर रहे हैं। कोई भी सभ्य नागरिक जिसे लोकशाही मुल्य, मानवीय गरिमा की सच्ची और सही समझ है। वे भारत में सरकार ने जो जनता पर युद्ध जारी किया है उसके जवाब में हथियार उठाना यह लाजमी और न्यायपूर्ण है यही कहेंगे और हथियारबंद संघर्ष कर रही जनता के पक्ष में खड़े होंगे। हम विभीन्न तबकों के तमाम जनपक्षधर और जनवादी लोगों से और जो अब तक जागे नहीं उनसे अपिल करते हैं कि, उठो भारत की सच्ची आजादी के लिए लड़ने वाली जनता के पक्ष में खड़े हो। देखो सरकारके यह बडे अफसरों के बोल इस बात द्योतक है की, वे इतना दमन करने के बावजूद भी जनता को जित नहीं सकें। यह उनके हारने के डर से निकल रही घबराहट का भौंकना है। दमन और घेराबंदी के बावजूद जनता डरी नहीं हैं। सोंच समझकर दिर्घकालीन जनयुद्ध की तर्ज पर अपने आप को मजबूत कर रही है। प्रचंड पुलिस घेराबंदी में भी अपनी पी.एल.जी.ए. को गुरिल्ला तर्ज से खाना-पानी पहुँचा रही है। सत्यपालसिंग गलती से एक सत्य कह गया कि जनता माओवादीयों के साथ है। इसलिए अब एक-दो की हत्या नहीं सारे गांव को मारना चाहता है। सत्यपालसिंग का धमकी भरा वक्तव्य उसकी बौखलाहट है। जनता पर आग उगलने वाले सत्यपालसिंग की हम भर्त्सना का करते हैं उनकी बात का खंडन करते हैं और उनके नापाक इरादों से जनताकी रक्षा अपनी जानपर खेलकर भी करेंगे।

कॉ. श्रिनिवास



सचिव

गडचिरोली डीवीजनल कमेटी